गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 051
दि. 20.06.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

काले कोट के संघर्ष को मिला न्याय: युवा वकीलों के भविष्य को संवारने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक पहल

देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में वकीलों की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही कठिन उनकी शुरुआती यात्रा भी होती है। अदालतों में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हजारों युवा अधिवक्ता ऐसे हैं जो कानून की डिग्री हासिल करने के बाद बड़े सपने लेकर इस पेशे में कदम रखते हैं, लेकिन वास्तविकता अक्सर उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण साबित होती है। शुरुआती वर्षों में आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता, मुवक्किलों का अभाव रहता है, कार्यालय की सुविधाएं नहीं मिलतीं और जीवन-यापन तक मुश्किल हो जाता है। कई प्रतिभाशाली युवा केवल आर्थिक कारणों से वकालत का पेशा छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इस गंभीर समस्या को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐसी पहल की है, जिसे भारतीय न्यायिक व्यवस्था में दूरगामी और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने युवा और जूनियर वकीलों की आर्थिक परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष सहायता कोष बनाने का सुझाव दिया है। अदालत का मानना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो देश की न्याय व्यवस्था को प्रतिभाशाली कानूनी दिमागों के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि आर्थिक तंगी के कारण युवा वकीलों का पेशा छोड़ना केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि न्यायिक व्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय है। यही कारण है कि शीर्ष अदालत ने 'यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंस फंड' के गठन का प्रस्ताव रखा है। यह मामला उस समय सामने आया जब महिला वकीलों के एक समूह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिका में युवा अधिवक्ताओं के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों, पेशे के शुरुआती संघर्षों और महिला वकीलों के लिए आवश्यक

सुविधाओं की कमी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। सुनवाई के दौरान अदालत ने महसूस किया कि यह समस्या केवल किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। न्यायालय ने कहा कि आर्थिक संघर्ष हर उस युवा वकील की वास्तविकता है जो पहली पीढ़ी से इस पेशे में आया है और जिसके पास पारिवारिक कानूनी विरासत या स्थापित नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। प्रधान न्यायाधीश Surya Kant और न्यायमूर्ति V. Mohan की पीठ ने इस विषय को केवल रोजगार या आय के प्रश्न के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे न्याय तक पहुंच और न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता से जुड़ा मुद्दा माना। अदालत ने कहा कि कानून का पेशा केवल आर्थिक रूप से सक्षम लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर युवा वकालत छोड़ने लगेंगे तो न्याय व्यवस्था की विविधता और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होंगी। भारत में हर वर्ष हजारों छात्र कानून की पढ़ाई पूरी करके वकालत के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की होती है जिनके परिवार का कानून से कोई संबंध नहीं होता। इन पहली पीढ़ी के वकीलों को शुरुआत से ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें न तो स्थापित कार्यालय मिलता है, न पर्याप्त संसाधन और न ही तुरंत मुवक्किल। अधिकांश युवा वकील किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ काम करते हैं और उन्हें जो मानदेय मिलता है, वह अक्सर इतना कम होता है कि उससे बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पातीं। कई मामलों में उन्हें परिवहन, किराया और भोजन जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। अदालत ने इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि कोई युवा अधिवक्ता लगातार आर्थिक दबाव में रहेगा तो उसके लिए लंबे समय तक पेशे में टिके रहना कठिन हो जाएगा। परिणामस्वरूप वह किसी अन्य क्षेत्र में रोजगार तलाशने को मजबूर हो सकता है। यही स्थिति 'ब्रेन ड्रेन' को जन्म देती है, जहां प्रतिभाशाली और प्रशिक्षित कानूनी दिमाग न्यायिक व्यवस्था से बाहर चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुझाव में एक संगठित और दीर्घकालिक सहायता प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। अदालत ने कहा कि युवा वकीलों के लिए बनने वाला कोष किसी अस्थायी योजना की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे कानूनी आधार और संस्थागत संरचना प्रदान की जानी चाहिए। न्यायालय का विचार है कि इस फंड का संचालन किसी हाई कोर्ट या केंद्र सरकार द्वारा गठित स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के माध्यम से किया जाए ताकि इसकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी वित्तीय संरचना है। अदालत ने सुझाव दिया कि देश के वरिष्ठ और सफल वकील इस फंड में नियमित रूप से योगदान दें। न्यायालय का मानना है कि जिन अधिवक्ताओं ने इस पेशे से प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त की है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे नई पीढ़ी की सहायता करें। साथ ही ऐसे योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट, राष्ट्रीय सम्मान और अन्य प्रोत्साहन भी दिए जा सकते हैं। अदालत ने केवल निजी योगदान पर निर्भर रहने के बजाय सरकारी भागीदारी की भी आवश्यकता बताई है। सुझाव दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें अदालतों में जमा होने वाली कोर्ट फीस का एक हिस्सा इस कोष में दें। इसके अतिरिक्त न्यायालयों द्वारा लगाए जाने वाले कुछ जुर्मानों की राशि भी इस फंड में जमा की जा सकती है। इससे कोष को स्थायी और मजबूत वित्तीय आधार मिल सकेगा। योजना के अनुसार जरूरतमंद और पहली पीढ़ी के युवा वकीलों को शुरुआती वर्षों में मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अदालत का मानना है कि पेशे के पहले तीन वर्ष सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होते हैं। इसलिए इस अवधि में दिया जाने वाला वजीफा इतना होना चाहिए कि युवा अधिवक्ता सम्मानपूर्वक अपनी आजीविका चला सके और पेशे में टिके रहने का आत्मविश्वास प्राप्त कर सके। इसके बाद अगले चार वर्षों में सहायता राशि को धीरे-धीरे कम किया जाएगा ताकि वकील आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सके। इस योजना की एक विशेषता यह भी है कि सहायता प्राप्त करने वाले अधिवक्ताओं को किसी वरिष्ठ वकील के साथ कार्य करना होगा। इससे उन्हें केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं मिलेगा, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण और पेशेवर मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं को समझने, मुकदमों की तैयारी करने और अदालतों में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए यह अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

विधान परिषद चुनाव के बाद भाजपा में मची हलचल क्रॉस वोटिंग के आरोपों ने बढ़ाई सियासी बेचैनी

कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। हाल ही में संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने न केवल राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी आत्ममंथन और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। चुनाव परिणामों के बाद भाजपा नेतृत्व को आशंका है कि कुछ विधायकों ने पार्टी के अधिकृत रुख से अलग जाकर मतदान किया, जिसके कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। यही वजह है कि पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को बेहद गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। आने वाले दिनों में यह रिपोर्ट कर्नाटक भाजपा की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विधान परिषद चुनाव सामान्यतः उतना ध्यान आकर्षित नहीं करते जितना विधानसभा या लोकसभा चुनाव करते हैं, लेकिन इस बार परिणामों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सात सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने पांच सीटों पर जीत हासिल कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जबकि भाजपा को केवल दो सीटों से संतोष करना पड़ा। सबसे बड़ा झटका भाजपा की सहयोगी जनता दल (सेक्युलर) को लगा, जो अपनी सीट बचाने में असफल रही। चुनाव परिणाम सामने आते ही राजनीतिक विश्लेषकों और नेताओं के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि कहीं गठबंधन के कुछ विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर मतदान तो नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष B. Y. Vijayendra ने इस विषय को हल्के में लेने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी के पास

कुछ ऐसी सूचनाएं पहुंची हैं जिनसे क्रॉस वोटिंग की आशंका मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी अनुशासन और संगठनात्मक निष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई जनप्रतिनिधि पार्टी के आधिकारिक निर्णय के विपरीत जाकर मतदान करता है तो यह केवल राजनीतिक असहमति का मामला नहीं बल्कि संगठनात्मक अनुशासन का प्रश्न भी बन जाता है। इसी संदर्भ में भाजपा ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इस समिति में पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और विधान परिषद सदस्य C. T. Ravi, पूर्व मंत्री N. Mahesh तथा विधायक Mahesh Tenginakai को शामिल किया गया है। समिति को चुनावी प्रक्रिया, मतदान पैटर्न और उपलब्ध सूचनाओं की समीक्षा कर 25 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से उन सभी सवालों के जवाब मिल सकेंगे जो चुनाव परिणामों के बाद उठे हैं।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि कर्नाटक में भाजपा और जेडी(एस) के बीच गठबंधन बनने के बाद यह पहला बड़ा अवसर है जब दोनों दलों की एकजुटता की वास्तविक परीक्षा हुई। गठबंधन की राजनीति में अक्सर विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच तालमेल बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। कई बार स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत समीकरण भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं केवल संख्या का सवाल नहीं बल्कि गठबंधन की मजबूती और भविष्य की राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं। चुनाव परिणामों के बाद कुछ विधायकों के नाम सार्वजनिक चर्चाओं में सामने आने लगे। राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। हालांकि भाजपा नेतृत्व ने इन चर्चाओं को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करने से इनकार किया है। विजयेंद्र ने स्पष्ट कहा कि पार्टी किसी अफवाह या राजनीतिक प्रचार के आधार पर कोई कदम नहीं उठाएगी। उनका कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर भाजपा के भीतर भ्रम और असंतोष का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रही है। इसलिए पार्टी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही कोई निष्कर्ष निकालेगी।

भाजपा का यह रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिना पर्याप्त साक्ष्य के कार्रवाई करने से संगठन के भीतर असंतोष पैदा हो सकता है। पार्टी नेतृत्व फिलहाल संयमित रणनीति अपनाते हुए जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही यह संदेश भी दिया जा रहा है कि यदि कोई विधायक पार्टी निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो क्रॉस वोटिंग का मुद्दा किसी भी दल के लिए संवेदनशील होता है। यह केवल चुनावी हार-जीत का मामला नहीं होता, बल्कि संगठन के भीतर विश्वास और निष्ठा की स्थिति को भी दर्शाता है। यदि किसी दल के विधायक या निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टी लाइन से हटकर मतदान करते हैं तो इससे नेतृत्व की पकड़, आंतरिक एकजुटता और राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि भाजपा इस पूरे मामले को गंभीर विश्वासघात के रूप में देख रही है। विजयेंद्र ने यह भी दावा किया कि क्रॉस वोटिंग की समस्या केवल भाजपा तक सीमित नहीं थी। उनके अनुसार सहयोगी दल जेडी(एस) के कुछ वोट भी गठबंधन उम्मीदवार को नहीं मिले। उन्होंने संकेत दिया कि गठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में जाने वाले छह से सात वोट जेडी(एस) से और चार से पांच वोट भाजपा से अपेक्षित रूप से नहीं मिले।

गरिमा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं: कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की बड़ी पहल

देश में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ कार्यस्थलों पर सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर का मुद्दा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, तकनीक, स्वास्थ्य, मीडिया और सेवा क्षेत्र सहित लगभग हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दे रही हैं। लेकिन इसके साथ ही कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और असुरक्षित वातावरण जैसी चुनौतियां भी समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे में महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक और संस्थागत दायित्व भी बन जाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत सलाह जारी की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यस्थल पर हर वर्ष पीओएसएच (POSH) ऑडिट कराना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। आयोग का मानना है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित समीक्षा की व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक है। यदि संस्थान समय-समय पर अपने सुरक्षा तंत्र, शिकायत निवारण व्यवस्था और संवेदनशीलता कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेंगे, तभी कार्यस्थलों को वास्तव में सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

यह सलाह देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों को भेजी गई है। साथ ही इसे जिला स्तर तक प्रभावी बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों तक भी पहुंचाया गया है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि आयोग केवल नीतिगत घोषणा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष Vijaya Rahatkar ने इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि किसी भी महिला को अपनी गरिमा और आजीविका के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार कार्यस्थल केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि ऐसा स्थान होना चाहिए जहां महिलाएं सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर के साथ अपने पेशेवर जीवन को आगे बढ़ा सकें। यह विचार आधुनिक कार्य संस्कृति के मूल सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें कर्मचारियों की गरिमा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए वर्ष 2013 में "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम" अर्थात पीओएसएच कानून लागू किया गया था।

संपादकीय

टेलीग्राम पर बैन

मई महीने में नीट प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद केंद्र सरकार अति- सतर्कता के मूड में नजर आ रही है। लीक प्रकरण के पश्चात निशाने पर आने के बाद सरकार कदम फूंक-फूंक कर रख रही है। इसी कड़ी में चर्चित मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लगाम लगाने के निर्णय को लेकर विवाद अदालत के दरवाजे तक जा पहुंचा है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये संघर्ष कर रही है। हकीकत यह है कि मई में प्रश्नपत्र लीक होने से मची अफरातफरी और विपक्ष के नेताओं के निशाने पर आने के बाद केंद्र सरकार कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। निस्संदेह, इस परीक्षा में आयोजक एजेंसियों की विश्वसनीयता और बीस लाख से ज्यादा प्रतिभागियों का भविष्य दांव पर लगा है। यही वजह है कि राष्ट्रीय महत्व की परीक्षाओं को लेकर नीट और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एटीए द्वारा परीक्षार्थियों का भरोसा फिर से कायम करने की कवायद पर पूरा जोर दिया जा रहा है। ऐसे में रविवार को होने वाली नीट की पुनःपरीक्षा से ठीक पहले, सरकार का चर्चित मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर कुछ अवधि के लिये प्रतिबंध लगाना, अति सतर्कता को ही दर्शाता है। सरकार के इस अतिरेक सावधानी वाले रवैये को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने अपने इस कदम का पुरजोर बचाव किया है। सरकार की दलील है कि इस क्लाउड-बेस्ड प्लेटफॉर्म का बॉट इंफ्रास्ट्रक्चर लीक हुई सामग्री का तेजी से बड़े पैमाने पर प्रसार करने में मददगार हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में देशवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पूरे प्लेटफॉर्म को कुछ दिनों के लिये ब्लॉक करने से आनुपातिकता और प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। लोगों का मानना है कि सतर्कता, सावधानी और तंत्र में सुधार कर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।

निस्संदेह, यदि किसी आपराधिक नेटवर्क द्वारा ऐप विशेष के दुरुपयोग की वजह से, उसके असली यूजर्स को परेशानी होती है तो इससे देश में गलत परंपरा की शुरुआत हो सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार दलील दे रहे हैं कि अगर किसी बड़ी परीक्षा हेतु टेलीग्राम की सेवाएं सस्पेंड की जा सकती हैं तो भविष्य में किसी अन्य मुद्दे पर दूसरे ऐप के विरुद्ध कार्रवाई को भी तार्किक ठहराया जा सकता है। फिर सत्ताधीशों को किसी अन्य ऐप पर अंकुश लगाने का अवसर बार-बार मिल सकता है। सरकारें कानून-व्यवस्था को खतरा बता कर, कार्रवाइयों को जायज ठहरा सकती हैं। तभी मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचने पर अदालत ने पूछा है कि 150 मिलियन यूजर्स के अधिकारों में कटौती कैसे की जा सकती है? आलोचक सरकार के रवैये को सिस्टम की विफलता बता रहे हैं। दलील है कि कोई भी प्रश्न पत्र तभी लीक होता हैं, जब परीक्षा से जुड़े कुछ अंदरूनी लोग नकल कराने वाले गिरोहों से मिल जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टेलीग्राम को ब्लॉक करने से समस्या खत्म नहीं होती है। इस प्रतिबंध के बाद यूजर्स आसानी से वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या दूसरे ऐप्स का सहारा ले सकते हैं। निस्संदेह, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग गलत कामों को अंजाम देने के लिये किया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से तकनीक की उपादेयता को खारिज नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर देश के दूर-दराज के इलाकों में प्रश्न-पत्रों को सुरक्षित पहुंचाने के लिये भारतीय वायु सेना को तैनात करने को एक सख्त कदम के रूप में देखा जा रहा है। जो सुरक्षा व्यवस्था को फुलप्रुफ बनाने की कवायद के रूप ध्यान तो खींचता है, लेकिन किसी स्थायी समाधान का विकल्प नहीं बन सकता । निस्संदेह, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और छात्रों का भरोसा जीतने के लिये सरकार द्वारा पूरी परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। किसी भी सरकार के लिये यही बेहतर होगा कि वह अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग बेहद पारदर्शी तरीके से और कम से कम करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनका गलत इस्तेमाल न हो सके।

सौ वर्षों से राष्ट्रसेवा में लीन RSS का पंजीकरण प्रमाणपत्र मांग रहे कांग्रेस नेताओं से कुछ सवाल

“ असल में कांग्रेस की समस्या संघ के पंजीकरण से नहीं, संघ के प्रभाव से है। जिस संगठन ने बिना सरकारी धन, बिना विदेशी सहायता और बिना सत्ता के सहारे सौ वर्षों तक राष्ट्रजीवन को दिशा दी हो, उससे कांग्रेस की बेचैनी स्वाभाविक है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कांग्रेस और उसके वैचारिक सहयोगियों ने एक बार फिर वही पुराना शोर उठाया है कि संघ पंजीकृत क्यों नहीं है? कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे का पत्र और उसके बाद खड़ा किया गया राजनीतिक कोलाहल इस बात का प्रमाण है कि संघ विरोधियों के पास न तथ्य बचे हैं, न तर्क। वह केवल विवाद पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस संगठन को जनता का भरोसा और समाज का समर्थन हासिल हो, उसे बदनाम करने का सबसे आसान तरीका संदेह फैलाना होता है।लेकिन इस बार संघ ने भी स्पष्ट और सीधा उत्तर दिया है। मोहन भागवत ने साफ कहा, “हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है।” यह उस पूरी मानसिकता पर प्रहार है जो मानती है कि भारत की हर सांस्कृतिक चेतना को सरकारी मुहर से ही वैधता मिलेगी। भागवत ने कहा कि संघ 1925 में स्थापित हुआ था। क्या तब अंग्रेजों से जाकर पंजीकरण कराया जाता? साथ ही स्वतंत्रता के बाद भी भारत के संविधान ने कभी यह अनिवार्य नहीं किया कि हर स्वैच्छिक संगठन सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो तभी वह अस्तित्व में रह सकता है।

असल में कांग्रेस की समस्या संघ के पंजीकरण से नहीं, संघ के प्रभाव से है। जिस संगठन ने बिना सरकारी धन, बिना विदेशी सहायता और बिना सत्ता के सहारे सौ वर्षों तक राष्ट्रजीवन को दिशा दी हो, उससे कांग्रेस की बेचैनी स्वाभाविक है। संघ ने चरित्र निर्माण किया, अनुशासन दिया, समाज को जोड़ा, सेवा का संस्कार दिया और राष्ट्रवाद को जीवन का व्यवहार बनाया। दूसरी ओर कांग्रेस का एक हिस्सा वर्षों तक विदेशी शक्तियों के सामने वैचारिक समर्पण करता रहा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौते करने वाली राजनीति आज संघ से राष्ट्रभक्ति का प्रमाण मांग रही है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। यह नागरिकों का मौलिक अधिकार है। संविधान कहीं नहीं कहता कि हर सामाजिक संगठन को पहले सरकार के सामने सिर झुकाकर अनुमति लेनी होगी। सोसाइटी कानून, न्यास कानून और अन्य व्यवस्थाएं केवल कानूनी सुविधाओं के लिए हैं, अस्तित्व के लिए नहीं।

संघ के पंजीकरण प्रमाणपत्र को देखने की चाह रखने वाले प्रियांक खरगे, पवन खेड़ा और कांग्रेस के नेताओं को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में मंत्री होना कानून से ऊपर होना नहीं होता। किसी मंत्री की व्यक्तिगत इच्छा कानून नहीं बन जाती। यदि कानून में अनिवार्यता नहीं है, तो केवल राजनीतिक नफरत के कारण किसी संगठन को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। यही विधि का शासन है, यही संविधान की आत्मा है।

संघ को समझने के लिए उसकी मूल प्रकृति को समझना आवश्यक है। संघ कोई पारंपरिक कार्यालयी संस्था नहीं, बल्कि समाज आधारित आंदोलन है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इसे सदस्यता कार्ड, शुल्क और कागजी ढांचे की बजाय शाखा, संस्कार और स्वयंसेवा के आधार पर खड़ा किया। आज भी कोई व्यक्ति शाखा में जाकर स्वयंसेवक बन सकता है। यही कारण है कि संघ समाज के बीच रहता है, किसी फाइल में बंद नहीं रहता। संघ अपने आरम्भकाल से ही सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ता रहा है। संघ में औपचारिक सदस्यता और कठोर संस्थागत नियंत्रण नहीं होता। शाखाएं अपने संसाधनों से चलती हैं और संगठन का संचालन सामाजिक सहभागिता से होता है।

इतिहास यह भी बताता है कि संघ को बार-बार राजनीतिक दमन का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगाया गया, आपातकाल में हजारों स्वयंसेवक जेल भेजे गए, बाबरी प्रकरण के बाद भी हमला हुआ। लेकिन हर बार संघ और अधिक मजबूत होकर निकला। इसका कारण यह था कि संघ की जड़ें सत्ता में नहीं, समाज में हैं। मोहन भागवत ने भी याद दिलाया कि सरकारें संघ पर प्रतिबंध लगाती रहीं, इसका अर्थ ही यह है कि सरकारें संघ के अस्तित्व और प्रभाव को मानती रही हैं।

देखा जाये तो संघ विरोधी बार बार पारदर्शिता और कराधान का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन वह जानबूझकर न्यायालयों के निर्णयों को नजरअंदाज करते हैं। “गुरु दक्षिणा” को लेकर न्यायालयों ने पारस्परिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया था। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट माना कि स्वयंसेवकों का स्वैच्छिक योगदान करयोग्य आय नहीं माना जा सकता। संघ ने कभी कानून से छूट नहीं मांगी। उसने केवल वही स्वीकार किया जो कानून कहता है। कानून जहां लागू होता है, वहां संघ के सहयोगी संगठन विधिवत पंजीकृत हैं, लेखा परीक्षण कराते हैं और अपने प्रतिवेदन भी प्रकाशित करते हैं।

यही वह बिंदु है जहां कांग्रेस का पाखंड खुलकर सामने आता है। दशकों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी आज संघ से पारदर्शिता मांग रही है, जबकि स्वयं उसके इतिहास पर आपातकाल, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विदेशी प्रभाव के आरोप लगे हुए हैं। जो दल लोकतंत्र को कुचलने के लिए आपातकाल थोप सकता है, वह आज लोकतांत्रिक मूल्यों का उपदेश दे रहा है। यह राजनीतिक हास्य से अधिक कुछ नहीं।

मोहन भागवत ने बिल्कुल सही कहा कि संघ खुलकर काम करता है, किसी गुप्त संगठन की तरह नहीं। लाखों शाखाएं, हजारों सेवा प्रकल्प, शिक्षा, ग्राम विकास, आपदा राहत, सामाजिक समरसता, वनवासी कल्याण, गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण, संघ का हर कार्य समाज के सामने है। यदि संघ में कुछ छिपा होता तो वह सौ वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में इतने व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता।

दरअसल संघ की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि उसने राष्ट्रवाद को केवल नारों तक सीमित नहीं रखा। जब भी देश पर संकट आया, स्वयंसेवक सबसे पहले खड़े दिखाई दिए। विभाजन के समय राहत कार्य हो, प्राकृतिक आपदाएं हों, महामारी का दौर हो या सीमा पर सैनिकों के परिवारों की सहायता, संघ के कार्यकर्ता हर जगह सक्रिय रहे। यही कारण है कि भारत का सामान्य नागरिक संघ को कागजी संस्था नहीं, राष्ट्रीय चेतना का प्रहरी मानता है।

संघ को लेकर सबसे अधिक भ्रम उन लोगों में है जो भारत को केवल सत्ता और चुनाव की नजर से देखते हैं। संघ सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए काम करता है। यही कारण है कि वह राजनीतिक उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है। मोहन भागवत ने हाल में कहा था कि संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, लेकिन सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला संगठन भी है। यह कथन बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने कभी शाखा देखी ही नहीं, वह संघ पर सबसे अधिक आरोप लगाते हैं।

देखा जाये तो आज आवश्यकता इस बात की है कि संघ को राजनीतिक चश्मे से नहीं, उसके कार्यों से देखा जाए। यदि कोई संगठन बिना सरकारी सहायता के, बिना विदेशी धन के और बिना सत्ता के दबाव के सौ वर्षों तक राष्ट्रसेवा करता है, तो उसकी वैधता किसी सरकारी रजिस्टर से नहीं, जनता के विश्वास से तय होती है।

कांग्रेस और संघ विरोधियों को यह समझ लेना चाहिए कि संघ को डराकर, बदनाम करके या कानूनी भ्रम फैलाकर कमजोर नहीं किया जा सकता। संघ की शक्ति कागजों से नहीं, करोड़ों स्वयंसेवकों के समर्पण से आती है। उसका अस्तित्व किसी मंत्री की कृपा पर नहीं, भारत की सांस्कृतिक आत्मा पर आधारित है। जो सौ वर्षों से राष्ट्र को सब कुछ दे रहा हो, उसे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्र स्वयं उसका परिचय बन जाता है।

साथ ही संघ को किसी वंशवादी राजनीति से चरित्र प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस संगठन ने सौ वर्षों तक बिना सत्ता, बिना सरकारी संरक्षण और बिना विदेशी सहारे के राष्ट्रजीवन को दिशा दी हो, उसकी पहचान किसी सरकारी मुहर से नहीं होती। संघ का परिचय उसके करोड़ों स्वयंसेवकों की तपस्या है, उसकी शाखाओं का अनुशासन है, उसकी सेवा का विस्तार है और भारत माता के प्रति उसका अखंड समर्पण है। राजनीतिक दल सत्ता से बनते और मिट जाते हैं, लेकिन संघ जैसी राष्ट्रशक्ति पीढ़ियों तक समाज की चेतना में जीवित रहती है। संघ को मिटाने के सपने देखने वाले आते जाते रहे, लेकिन संघ आज भी उतना ही दृढ़, उतना ही प्रभावशाली और उतना ही राष्ट्रनिष्ठ खड़ा है, क्योंकि उसका आधार सत्ता नहीं, भारत की सनातन आत्मा है।

बहरहाल, जिस संगठन के स्वयंसेवक प्रतिदिन यही मंत्र जपते हों, “तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें ना रहें”, उससे अपना पंजीकरण कराने को कहना कांग्रेस नेताओं की राजनीतिक हताशा ही नहीं, बल्कि उनकी बेवकूफी भी प्रदर्शित करता है।

प्रेरणा

मीठे शब्दों का छिपा हुआ ज़हर

मनुष्य के जीवन में शब्दों का बहुत महत्व होता है। शब्द किसी टूटे हुए मन को संबल दे सकते हैं, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगा सकते हैं और किसी साधारण व्यक्ति को महान बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। लेकिन यही शब्द यदि स्वार्थ, छल और चापलूसी से भरे हों तो वे किसी विष से कम नहीं होते। इतिहास और अनुभव दोनों इस बात के साक्षी हैं कि तलवार से होने वाले घाव समय के साथ भर जाते हैं, किंतु झूठी प्रशंसा और चापलूसी से होने वाली हानि व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देती है। इसी सत्य को स्पष्ट करने वाली एक अत्यंत शिक्षाप्रद कथा है।

एक बार एक प्रतापी राजा अपने राजदरबार में विराजमान थे। दरबार में राज्य के श्रेष्ठ विद्वान, मंत्री, सेनापति और राजगुरु उपस्थित थे। राजा को ज्ञान प्राप्त करने की बड़ी इच्छा रहती थी। वे समय-समय पर ऐसे प्रश्न पूछते थे जिनसे केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों का भी उद्घाटन होता था।

उस दिन भी राजा के मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने दरबार में उपस्थित विद्वानों की ओर देखकर पूछा, “बताइए, संसार में सबसे तेज काटने वाला और सबसे अधिक विषैला कौन होता है?”

राजा का प्रश्न सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी विद्वान अपने-अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उत्तर सोचने लगे।

सबसे पहले एक विद्वान खड़ा हुआ और बोला, “महाराज, मेरी दृष्टि में ततैया सबसे अधिक काटने वाला और पीड़ादायक जीव है। इसके डंक का दर्द मनुष्य को लंबे समय तक परेशान करता है।”

राजा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष दिखाई नहीं दिया।

तभी दूसरे विद्वान ने कहा, “राजन, मधुमक्खी का डंक अत्यंत कष्टदायक होता है। यदि अनेक मधुमक्खियां एक साथ हमला कर दें तो मनुष्य का जीवन भी संकट में पड़ सकता है।”

राजा ने यह उत्तर भी सुना, परंतु उनकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई।

तीसरे विद्वान ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, “महाराज, बिच्छू का डंक सबसे खतरनाक होता है। उसका विष मनुष्य को असहनीय पीड़ा देता है।”

चौथे विद्वान ने तुरंत कहा, “राजन, इन सबसे अधिक भयंकर तो सांप होता है। सांप का काटा हुआ व्यक्ति पानी तक नहीं मांग पाता। उसके विष की तुलना किसी से नहीं की जा सकती।”

दरबार में उपस्थित अनेक लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें लगा कि यही सही उत्तर होगा। लेकिन राजा के चेहरे पर अब भी संतोष के भाव नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि प्रश्न का वास्तविक उत्तर अभी सामने नहीं आया है।

अंततः उन्होंने सिंहासन के समीप विराजमान राजगुरु की ओर देखा। राजगुरु अपने ज्ञान, अनुभव और गहन दृष्टि के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। राजा ने विनम्रता से कहा, “गुरुदेव, अब आप ही इस प्रश्न का समाधान कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप इसका सही उत्तर देंगे।”

राजगुरु मुस्कुराए। उन्होंने कुछ क्षण मौन धारण किया और फिर बोले, “राजन, मेरी दृष्टि में संसार में सबसे अधिक विषैले दो प्रकार के लोग होते हैं—एक निंदक और दूसरा चाटुकार।”

राजा सहित पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। सभी एक-दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उत्तर किसी जीव-जंतु का नहीं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव का होगा।

राजा ने आदरपूर्वक पूछा, “गुरुदेव, कृपया विस्तार से समझाइए। निंदक और चाटुकार किसी सांप या बिच्छू से अधिक विषैले कैसे हो सकते हैं?”

राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, “राजन, निंदक के हृदय में द्वेष और ईर्ष्या का विष भरा रहता है। वह सामने से नहीं, बल्कि पीछे से वार करता है। वह किसी व्यक्ति की अच्छाइयों को नहीं देखता, केवल उसकी कमियों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। उसकी निंदा लोगों के मन में भ्रम और अविश्वास पैदा करती है। उसका विष धीरे-धीरे संबंधों को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार कोई छिपा हुआ रोग शरीर को भीतर से खोखला कर देता है, उसी प्रकार निंदा समाज और परिवार को भीतर से कमजोर कर देती है।”

दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया।

राजगुरु आगे बोले, “लेकिन निंदक से भी अधिक खतरनाक चाटुकार होता है। निंदक का विष तो दिखाई दे जाता है, क्योंकि उसकी बातों में कटुता होती है। किंतु चाटुकार का विष मीठा होता है। वह व्यक्ति के सामने उसकी इतनी प्रशंसा करता है कि वह स्वयं को वास्तविकता से अधिक महान समझने लगता है।”

राजा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे।

राजगुरु ने कहा, “चाटुकार कभी सत्य नहीं बोलता। उसका उद्देश्य केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। वह व्यक्ति की कमजोरियों को छिपाकर उन्हें गुणों का रूप दे देता है। यदि किसी में अहंकार है तो वह उसे आत्मविश्वास बताता है। यदि किसी में क्रोध है तो उसे वीरता कहता है। यदि किसी में जिद है तो उसे दृढ़ संकल्प का नाम देता है। धीरे-धीरे व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानना बंद कर देता है।”

उन्होंने आगे कहा, “राजन, जब मनुष्य अपनी गलतियों को देखना छोड़ देता है, तभी उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। चाटुकार की बातें सुनकर व्यक्ति अहंकार के नशे में डूब जाता है। उसे लगता है कि वह जो भी कर रहा है, वही सही है। उसके आसपास सत्य बोलने वाले लोग दूर होने लगते हैं और केवल स्वार्थी लोग ही रह जाते हैं।”

राजा के मन में अनेक घटनाएं घूमने लगीं। उन्हें याद आया कि कई बार राजाओं का पतन बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि दरबार के चाटुकारों के कारण हुआ था।

राजगुरु ने कहा, “इतिहास में अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने सत्य बोलने वाले सलाहकारों की उपेक्षा की और चाटुकारों को महत्व दिया। परिणामस्वरूप वे वास्तविक परिस्थितियों से अनजान हो गए और अंततः उनका राज्य नष्ट हो गया। चापलूसी व्यक्ति के विवेक को काट देती है। जब विवेक नष्ट हो जाता है, तब निर्णय लेने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है।” फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, “जो व्यक्ति आपकी कमियों की ओर विनम्रता से ध्यान दिलाता है, वह आपका सच्चा हितैषी है। लेकिन जो हर समय आपकी झूठी प्रशंसा करता है, वह आपका मित्र नहीं, बल्कि आपके पतन का मार्ग तैयार कर रहा होता है।”

राजा अब पूरी तरह संतुष्ट हो चुके थे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर ही नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी मिल गया था।

हिंदी पत्रकारिता के आकाश में ‘छत्तीसगढ़ मित्र’ की दीप्ति

अपने रायपुर (छत्तीसगढ़) शहर में पत्रकारिता के दो-एक आयोजनों से गुज़रने के बाद देखा कि पूर्वज परंपरा अब स्मृति-लोप का अधिक शिकार है। ठीक उस वक्त जब हिंदी पत्रकारिता के दो सौ वर्षों का कालखंड (सन् 1826 में कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा हिंदी साप्ताहिक ‘उदंत मार्तण्ड’ का प्रकाशन) सामने है तब खुशी और हैरानी एक साथ सामने उभर आई है। देश में अलग-अलग जगह होने वाले आयोजनों ने बताया कि वे लोग बंगाल की भूमि से उठे एक व्यक्ति के ‘उस अवदान’ को प्रणति दे रहे हैं - जिसे आज ‘पत्रकारिता’ जैसे सम्मान जनक पेशे के रूप में दुनिया जानती है। उनकी याद, सिर्फ़ भावुक याद नहीं, आज के समय में दो सौ वर्षों के इस वृहद कालखंड के बीत जाने के बाद ख़ुद को खंगालने जैसा भी है।

‘माधवराव सप्रे’ इस नाम से पहला परिचय स्कूली दौर में हुआ था। कारण था इस नाम वाली उस पाठशाला में हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए भर्ती होना। कोई बड़ी मालूमात नहीं थी कि इस नाम का जो महत्व है वही आगे चलकर मेरी अपनी पहचान का कारण बनेगा। अर्थात् लिखने-पढ़ने वाला जीवन। बरसों बाद, जब डॉ. अशोक सप्रे से परिचय हुआ तो धीरे-धीरे जाना कि जिन माधवराव सप्रे नाम के स्कूल में तीन वर्ष बिताए उनका असल परिचय क्या था। उन्नीसवीं सदी (19 जून, सन् 1871 में जन्म) वाले माधवराव सप्रे के परिवार से जुड़ा वर्तमान सदी का कोई सदस्य सामने सहज सुलभ था, उनके घर भी आवाजाही थी। बावजूद सप्रेजी का कहा या प्रकाशन जो अनकहा हो इस बाबत डॉ. सप्रे बता सकते थे उस तथ्य से परिचित होने से चूक गया। इतने बरसों बाद जब हम पत्रकारिता के एक बिल्कुल अलग दौर में खड़े हैं तब संत मन वाले माधवराव सप्रे का योगदान हैरानी में डालता है!

उस काल में, जब इस विधा विशेष के लिए न तो ठिकाने के उदाहरण थे न ही रास्ते सुलभ थे तब एक आदमी जो स्वयं अनजान था असाधारण साहस करने सामने आता है! पत्रिका कैसे चलेगी इसका कोई पूर्वानुभव नहीं था अलबत्ता हौसला कम न था। लेकिन तीन वर्ष की अवधि तक निरन्तर घाटा होते रहने के कारण मजबूरन प्रकाशन रोकना पड़ा। छोटी आयु मिली थी ‘छत्तीसगढ़ मित्र’ को। मात्र तीन साल। सन् 1900 के पहले महीने सप्रे जी पत्रकारिता की अपनी वह योजना धरातल पर उतारते हैं। संघर्ष करते-करते अंततः तीसरे वर्ष पत्रिका का प्रकाशन रोकना पड़ जाता है। जबकि पत्रिका की गुणवत्ता का मानदंड समझने को प्रयाग से निकलने वाली ‘सरस्वती’ की ओर देखना चाहिए जिसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन् 1903 में संपादक का भार संभालने के बाद ठीक उसी भावभूमि पर ढाला था जिस पर ‘छत्तीसगढ़ मित्र’ का वैचारिक आधार टिका हुआ था।

‘छत्तीसगढ़’ नाम को सामने रखने का विचार किस क़दर गहरा था! गैर हिंदी भाषी (मराठी मूल का) एक साधक रचनाकार समाज को हिंदी में कुछ देने की नीयत से निकलता है और उस ‘छत्तीसगढ़’ को, जो तब एक अंचल मात्र था, के लिए इस अखबार को ‘मित्र’ के रूप में देखता है। आज भले ‘सप्रे रचनावली’ हमारे सामने पत्रकारिता के उस युग को विस्तार से समझने का ज़रिया हो। इसके समानांतर सन् 2022 में साहित्य अकादमी, नई दिल्ली से आई ‘भारतीय साहित्य के निर्माता : माधव राव सप्रे’ किताब नई पीढ़ी को जरूर पढ़नी चाहिए। यह किताब पत्रकारिता को समझने की एक पोथी तो है, साथ में व्यक्ति विशेष के अवदान को भी समझाती है। पत्रिका के पहले अंक में संवाददाताओं की नियुक्ति के लिए सप्रे जी इच्छुकों से आग्रह करते रोचक ढंग लिखते हैं कि,’मेहनती और ईमानदार की दरकार है। गपोड़ी आदमी नहीं चाहिए!’ इसके उलट आज की पत्रकारिता का सारा दारोमदार ही उस ‘सप्रे भाव’ से छत्तीस के आंकड़े पर है!

‘छत्तीसगढ़ मित्र’ जिस काल में अपने नगण्य साधनों से सामने आया तब न तो जीवन में रंग दाख़िल थे और न मानव देह का हिस्सा थे। इस नई सदी में भारत के विकास का अश्वमेध घोड़ा जब दुनिया की परिक्रमा कर रहा हो तब भी यानी सन् 2026 में भी पं. माधवराव सप्रे के उसी ‘छत्तीसगढ़ मित्र’ का जीवन खुशहाल नहीं है! सन् 2009 से दोबारा प्रकाशित हो रही इस पत्रिका के सम्मुख चुनौतियां जस की तस हैं! अलबत्ता अच्छी सामग्री की बदौलत ही वह जी रही है। दूसरी पत्रिकाओं से स्पर्धा के लिए भी उसके पास कोई आधार नहीं। उसकी ताक़त सहजता है। बिना फोटो वाला रूप उसका पहचान पत्र है। ग्राफिक्स बेस्ड ले-आउट, मल्टी कलर के समय में बिना चमक, बिना किसी गर्जना के टिका रहना क्या उपलब्धि नहीं मानी जाएगी?

वर्तमान हिंदी पत्रकारिता आर्थिक नवजागरण में हिलोरे ले रही है। जबकि सप्रे जी ने सन् 1900 में इसे हिंदी-नवजागरण की दिशा में एक प्रस्थान बिंदु की तरह देखा-दिखाया। आज इक्कीसवीं शताब्दी संसाधनों के अतिरेक की शताब्दी है। बदलाव स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस शताब्दी के आरम्भ होने के साथ पत्रकारिता ने उपलब्धियों और कामयाबी की असाधारण डगर भी पार की। भारत में मीडिया का उजला चेहरा उसकी ताक़त बना है। कस्बों में पत्र-पत्रिकाओं की फौज दिखाई देती है।

अब एक-एक अक्षरों को जोड़ने वाली धीमी छपाई वाले स्याही युग से हम कोसों दूर निकल आए। डिजिटल-स्क्रीन और यह समय तो उसके भी ऊपर एआई का है। ‘कृत्रिम मेधा’ का इस्तेमाल भी स्वस्थ पत्रकारिता की राह में नया रोड़ा है। कभी स्वाधीनता इसका धर्म था। बाद में आज़ाद भारत का बढ़ता कद इसने देखा-दिखाया। नई सदी ने इसके दशानन रूप से भी परिचय कराया। याद रखना चाहिए, खासकर आजकल के मीडिया को कि हम कोई भी काम करें, उसमें नत्थी विनय भाव ही हमें और हमारे काम को विनयशील पहचान देता है, मानवीय बनाता है।

‘छत्तीसगढ़ मित्र’ ने इसी विनय भाव को अपना मूल स्वर बनाया, जो माधवराव सप्रे के दौर में था।

अभियान

रस्सी नहीं, मोक्ष का सूत्र: क्यों जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए उमड़ पड़ता है आस्था का सागर

जब आषाढ़ मास का पावन समय आता है, तब ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ की नगरी एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठती है। समुद्र की लहरों के बीच बसी यह पवित्र भूमि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन जाती है। दूर-दूर से आए भक्तों की आंखों में केवल एक ही इच्छा होती है—भगवान जगन्नाथ के दर्शन और उनके रथ की रस्सी को स्पर्श करने का सौभाग्य। जैसे ही विशाल रथों के पहिए आगे बढ़ते हैं और हजारों हाथ एक साथ रस्सियों को थामते हैं, पूरा वातावरण “जय जगन्नाथ” के जयघोष से गूंज उठता है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ईश्वर और भक्त के बीच प्रेम, समर्पण और विश्वास का ऐसा महासंगम है, जिसकी तुलना संसार में किसी अन्य उत्सव से करना कठिन है।

पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा को भारत की सबसे प्राचीन और भव्य धार्मिक परंपराओं में गिना जाता है। सदियों से चली आ रही यह यात्रा आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। सामान्यतः मंदिरों में भक्त भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा में यह परंपरा उलट जाती है। यहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि इसे करुणा, प्रेम और समानता का उत्सव भी कहा जाता है।

भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण का स्वरूप माना जाता है। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी रथों पर विराजमान होकर यात्रा करते हैं। तीनों देवताओं के लिए अलग-अलग रथ बनाए जाते हैं, जिनका निर्माण हर वर्ष नए सिरे से किया जाता है। यह परंपरा अपने आप में अद्वितीय है। जहां दुनिया के अधिकांश धार्मिक स्मारकों में स्थायी संरचनाओं का उपयोग होता है, वहीं जगन्नाथ संस्कृति हर वर्ष नए रथ निर्माण के माध्यम से सृष्टि के नवीनीकरण और परिवर्तन के सिद्धांत को दर्शाती है।

भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष कहलाता है। यह तीनों रथों में सबसे विशाल और भव्य होता है। इसके साथ बलभद्र का तलध्वज और सुभद्रा का दर्पदलन रथ चलता है। इन रथों को बनाने में विशेष प्रकार की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है और पारंपरिक शिल्पकार कई महीनों तक दिन-रात मेहनत करके इन्हें तैयार करते हैं। निर्माण प्रक्रिया में वैदिक विधानों का पालन किया जाता है, जिससे यह केवल एक शिल्प कार्य नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठान बन जाता है।

रथ यात्रा का सबसे रहस्यमय और आकर्षक पक्ष रथ की रस्सी से जुड़ा हुआ है। लाखों लोग केवल इसलिए पुरी पहुंचते हैं कि उन्हें कुछ क्षण के लिए उस रस्सी को पकड़ने का अवसर मिल जाए। पहली नजर में यह सामान्य लग सकता है कि लोग एक रथ को खींचने के लिए इतनी उत्सुकता क्यों दिखाते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरी धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक दर्शन छिपा हुआ है।

सनातन परंपरा के अनुसार भगवान के रथ की रस्सी खींचना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति से रथ खींचने वाला व्यक्ति भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है। उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग मिलता है। यह केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से रथ को मानव शरीर का प्रतीक माना गया है। भगवान उस शरीर में स्थित आत्मा के समान हैं और रस्सी मनुष्य के कर्मों तथा संकल्पों का प्रतिनिधित्व करती है। जब भक्त रथ को आगे बढ़ाते हैं, तो उसका अर्थ यह होता है कि वे अपने जीवन को ईश्वर की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि मनुष्य को अपने जीवन रूपी रथ को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलाना चाहिए।

जगन्नाथ संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है—समानता। रथ यात्रा के दौरान किसी की जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या सामाजिक स्थिति नहीं देखी जाती। रथ की रस्सी पर हाथ रखने वाले सभी लोग समान माने जाते हैं। कोई राजा हो, उद्योगपति हो, साधु हो, किसान हो या मजदूर, सभी एक ही रस्सी को पकड़कर भगवान की सेवा करते हैं। यह दृश्य भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा को जीवंत कर देता है जिसमें समस्त मानवता को एक परिवार माना गया है।

रथ यात्रा के दौरान होने वाली एक विशेष परंपरा “छेरा पहंरा” इस समानता के संदेश को और भी सशक्त बनाती है। इस रस्म में पुरी के गजपति महाराज स्वयं स्वर्ण झाड़ू लेकर भगवान के रथों की सफाई करते हैं। यह परंपरा बताती है कि ईश्वर के समक्ष कोई बड़ा या छोटा नहीं है। सत्ता, धन और पद का अहंकार भगवान के द्वार पर समाप्त हो जाता है। वहां केवल भक्ति और सेवा का महत्व होता है।

जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध केवल धार्मिक आस्था से नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से भी है। मान्यता है कि यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। गुंडिचा मंदिर को उनकी मौसी का घर माना जाता है। वहां वे कुछ दिनों तक निवास करते हैं और फिर बहुदा यात्रा के माध्यम से वापस श्रीमंदिर लौटते हैं। यह परंपरा भगवान को एक ऐसे पारिवारिक स्वरूप में प्रस्तुत करती है जो भक्तों के बहुत निकट है। वे केवल पूजनीय देवता नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह अनुभव किए जाते हैं। रथ यात्रा के दौरान पुरी की सड़कों पर जो दृश्य दिखाई देता है, वह अविस्मरणीय होता है। लाखों लोगों की भीड़, शंखों की ध्वनि, मृदंग और झांझ की गूंज, भजनों की मधुर स्वर लहरियां और चारों ओर फैली भक्ति की ऊर्जा वातावरण को दिव्य बना देती है। श्रद्धालु घंटों धूप में खड़े रहकर भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही रथ आगे बढ़ता है, लोगों की आंखों में आंसू और चेहरों पर आनंद की चमक दिखाई देने लगती है।

यह यात्रा केवल भारत तक सीमित नहीं रही है। आज दुनिया के अनेक देशों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं आयोजित की जाती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस और अन्य देशों में भी हजारों लोग इस परंपरा में भाग लेते हैं। विदेशी भक्त भी उसी श्रद्धा के साथ भगवान के रथ को खींचते हैं जिस श्रद्धा से भारतीय भक्त करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान जगन्नाथ का संदेश किसी एक क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है।

जगन्नाथ शब्द का अर्थ ही है—जगत का नाथ, अर्थात समस्त संसार का स्वामी। इसलिए उनकी रथ यात्रा भी विश्वबंधुत्व और सार्वभौमिक प्रेम का संदेश देती है। जब लाखों लोग एक साथ रथ खींचते हैं तो वहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। सभी का लक्ष्य केवल एक होता है—भगवान की सेवा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो रथ यात्रा मनुष्य के जीवन का भी प्रतीक है। संसार एक यात्रा है, शरीर एक रथ है और आत्मा उसका यात्री। जीवन के मार्ग पर अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जब मनुष्य ईश्वर को अपना मार्गदर्शक बना लेता है तो उसका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। रथ की रस्सी खींचना इसी सत्य का प्रतीकात्मक प्रदर्शन है।

आज के आधुनिक युग में जहां भौतिकता और प्रतिस्पर्धा ने जीवन को जटिल बना दिया है, वहां जगन्नाथ रथ यात्रा लोगों को प्रेम, सेवा, विनम्रता और समर्पण का संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की वास्तविक शांति धन, शक्ति या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति आस्था और मानवता की सेवा में निहित है। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पुरी की ओर खिंचे चले आते हैं। वे केवल एक उत्सव में भाग लेने नहीं आते, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव को जीने आते हैं जो उनके हृदय को बदल देता है। भगवान के रथ की रस्सी उनके लिए केवल मोटी डोर नहीं होती, बल्कि वह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम, आस्था का सूत्र और मोक्ष की आशा का प्रतीक बन जाती है।

जब भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ आगे बढ़ता है और लाखों हाथ उसकी रस्सी को थामते हैं, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं मानवता ईश्वर की ओर बढ़ रही हो। यही जगन्नाथ रथ यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे महान संदेश है—भगवान दूर नहीं हैं, वे अपने भक्तों के बीच हैं, उनके साथ हैं और उन्हें अपने प्रेम के रथ पर बैठाकर जीवन के परम लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए सदैव तत्पर हैं।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

‘गरवी गुर्जरी’ ने वोकल फॉर लोकल के विजन को दिया वेग : पाँच वर्षों में 123 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री

▶▶ 2025–26 में 43.07 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री के साथ रचा गया इतिहास, गुजरात की समृद्ध हथकरघा-हस्तकला विरासत को मिली नई ऊँचाई

▶▶ कारीगरों को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ रहा है ‘गरवी गुर्जरी’ मंच

गांधीनगर : गुजरात के हथकरघा एवं हस्तकला उत्पाद केवल वस्तुएँ नहीं हैं, बल्कि राज्य की संस्कृति, सृजनात्मकता तथा कारीगरों के कौशल का जीवंत प्रतिबिंब हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन के अनुरूप तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार परंपरागत कलाओं को नई पहचान, व्यापक बाजार और आर्थिक शक्ति प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। इन प्रयासों में गुजरात राज्य हथकरघा एवं हस्तकला विकास निगम (जीएसएचएचडीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित ‘गरवी गुर्जरी’ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

गरवी गुर्जरी ने वर्ष 2025-26 के दौरान अपने 53 वर्षों के इतिहास में पहली बार 43.07 करोड़ रुपए की सर्वाधिक बिक्री दर्ज कर नया इतिहास रचा है। पिछले पाँच वर्षों के आँकड़े देखें, तो कुल 123.88 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री कर गरवी गुर्जरी ने गुजरात के हथकरघा एवं हस्तकला क्षेत्र को नई ऊँचाई पर पहुँचाया है। इसमें वर्ष 2021-22 में 11.50 करोड़ रुपए, वर्ष 2022-23 में 12.00 करोड़ रुपए, वर्ष 2023-24 में 25.20 करोड़ रुपए, वर्ष 2024-25 में 32.09 करोड़ रुपए और वर्ष 2025-26 में 43.07 करोड़ रुपए की बिक्री शामिल है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि यदि परंपरागत कला को उचित दिशा, सुदृढ़ नीति तथा आधुनिक बाजार का सहयोग मिले, तो वह आर्थिक विकास का सशक्त आधार बन सकती है। यह सफलता केवल आँकड़ों तक सीमित नहीं है, अपितु हजारों कारीगरों के आत्मविश्वास, कौशल एवं परिश्रम की भी सशक्त अभिव्यक्ति है।

देश-विदेश तक पहुँचा ब्रांड, कारीगरों को आर्थिक बल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में गरवी गुर्जरी ने वर्ष 2025-26 के दौरान अपने साथ जुड़े हुए लगभग 8 हजार कारीगरों से 16.01 करोड़ रुपए के उत्पादों की खरीद कर उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक बल प्रदान किया है। राज्य व राज्य के बाहर संचालित 22 एम्पोरियमों द्वारा 20.77 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है, जबकि देश-विदेश में आयोजित विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों द्वारा 22.30 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि गरवी गुर्जरी अब केवल एक क्षेत्रीय ब्रांड नहीं, बल्कि राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुजरात की कला एवं हस्तकला की पहचान बन रहा है।

कारीगरों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के निरंतर प्रयास

राज्य सरकार ने कारीगरों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कारीगरों को आधुनिक डिजाइन, नई टेक्नोलॉजी और बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही; मार्केटिंग के लिए अधिक अच्छे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी कला को उचित मूल्य एवं व्यापक पहचान मिल सके। ये प्रयास परंपरागत कला को आधुनिक जीवनशैली तथा वैश्विक बाजार के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

गरवी गुर्जरी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने परंपरागत कला को केवल संरक्षित करने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे आधुनिक आवश्यकताओं और बाजार की मांग के अनुसार ढालकर उसकी उपयोगिता तथा मांग; दोनों में वृद्धि की है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कारीगरों को समान अवसर मिलने से उनकी आय में वृद्धि हुई है और उनके जीवनस्तर में भी सकारात्मक परिवर्तन आया है।

अगले वर्ष अत्याधुनिक प्रशिक्षण और नए बाजारों पर बल

वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार एवं निगम ने और महत्वाकांक्षी आयोजन किया है। इसके तहत कारीगरों को अत्याधुनिक टेक्निकल प्रशिक्षण देने, नए एवं आकर्षक उत्पाद विकसित करना, उत्पादों की व्यापक खरीद सुनिश्चित करना एवं राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मेलों में अधिक भागीदारी द्वारा नए बाजारों तक पहुँच बनाना जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य कारीगरों की आय, रोजगार एवं सामाजिक सम्मान में निरंतर वृद्धि करना है।

धर्मिष्ठाबेन चुडासमा के उत्पादों को मिली देशव्यापी पहचान

अहमदाबाद की कढ़ाई-बुनाई (एम्ब्रॉइडरी) कारीगर धर्मिष्ठाबेन चुडासमा कहती हैं कि वे कई वर्षों से गरवी गुर्जरी से जुड़ी हुई हैं। पहले उनके उत्पादों की बिक्री केवल स्थानीय स्तर पर ही होती थी, परंतु गरवी गुर्जरी द्वारा आयोजित मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने का अवसर मिलने से उनकी कला गुजरात के अलावा देश के विभिन्न राज्यों तक पहुँची है।

वे कहती हैं कि गरवी गुर्जरी द्वारा उनके उत्पादों की खरीद कर देशभर के एम्पोरियमों में बिक्री की जाती है, जो उनके लिए गर्व की बात है। प्रदर्शनियों के दौरान कला-प्रेमी उपभोक्ताओं के साथ प्रत्यक्ष संपर्क होने से उन्हें कस्टमाइज्ड ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। इसके परिणामस्वरूप उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

कारीगरों के उत्थान के लिए लगातार कार्यरत गरवी गुर्जरी

गुजरात राज्य हथकरघा एवं हस्तकला विकास निगम लिमिटेड, गांधीनगर के एक अधिकारी ने कहा कि गरवी गुर्जरी लगातार कारीगरों के उत्थान के लिए कार्यरत है। उत्पादों की खरीद, मार्केटिंग सहायता तथा प्रतिष्ठित प्रदर्शनियों में भाग लेने का अवसर प्रदान कर कारीगरों को प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही; कौशल विकास प्रशिक्षण और डिजाइन विकास कार्यशालाओं द्वारा कारीगरों को आधुनिक बाजार की मांग के अनुसार सशक्त बनाया जा रहा है। गरवी गुर्जरी के प्रतिभाशाली कारीगरों की आजीविका को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गरवी गुर्जरी आज केवल एक ब्रांड नहीं है; बल्कि गुजरात की समृद्ध कला, संस्कृति तथा कारीगरों की प्रतिभा का सशक्त प्रतीक बन गई है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों, मजबूत नेतृत्व और कारीगरों के अविरत परिश्रम के समन्वय से गुजरात ने सिद्ध किया है कि ‘विकास भी, विरासत भी’ केवल एक मंत्र नहीं; बल्कि विरासत के संरक्षण के साथ विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करने का सफल मॉडल भी है।

राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल नवसारी की खेरगाम तहसील के आछवणी गाँव में सफाई अभियान में सहभागी हुए : स्वयं कचरा साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया

▶▶ स्वच्छता केवल बाह्य सफाई नहीं, बल्कि एक जीवनशैली एवं संस्कार है : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी

▶▶ ग्रामीणजन-युवा तंबाकू, गुटखा, पानमसाले का सेवन पूर्णतः बंदकर पौष्टिक भोजन लें; निर्व्यसनी तथा संस्कारवान बनकर गाँव, राज्य और देश का गौरव बढ़ाएँ : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल नवसारी जिले की खेरगाम तहसील के आछवणी गाँव में सफाई अभियान में सहभागी हुए और उन्होंने ग्रामीणजनों के साथ झाड़ू से स्वयं कचरा साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वच्छता का महत्व समझाते हुए कहा कि स्वच्छता केवल बाह्य सफाई नहीं है, बल्कि एक जीवनशैली एवं संस्कार है। स्वच्छ भारत राष्ट्र निर्माण की नींव है। ‘जहाँ स्वच्छता, वहाँ स्वास्थ्य’; इस न्याय से स्वच्छता से समाज स्वस्थ बनेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। राज्यपाल ने प्रत्येक नागरिक का अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखकर ‘स्वच्छता ही सेवा’ के मंत्र को चरितार्थ करने तथा समृद्ध व गौरवशाली भारत का निर्माण करने में अपना योगदान देने का आह्वान किया और प्राकृतिक खेती का महत्व बताते हुए उपस्थित ग्रामीणजनों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।

राज्यपाल ने आछवणी गाँव स्वच्छ और सुगठित बने, गाँव में भाईचारा, सद्भाव, एकता बने रहें; इसके लिए सामूहिक प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वच्छता को स्वभाव बनाने तथा खुले में शौच जाने वाले ग्रामीणजनों के लिए देशव्यापी स्वच्छता आंदोलन चलाया और आज देश के करोड़ों घर शौचालय से युक्त बने हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि आछवणी गाँव स्वच्छ एवं सुगठित बने; इसके लिए सभी मिलकर स्वच्छता को प्राथमिकता दें। ग्रामीणजनों को सचेत करते हुए कहा कि ग्रामीणजन तथा विशेष रूप से युवा तंबाकू, गुटखा, पानमसाले का सेवन पूर्णतः बंदकर पौष्टिक भोजन लें तथा निर्व्यसनी और संस्कारवान बनकर गाँव, राज्य और देश का गौरव बढ़ाएँ। विकास तथा समृद्धि की आकांक्षा ही ‘विकसित गुजरात से विकसित भारत@2047’ के गुजरात के विजन को साकार करने में सहायक होगी।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गाँव के दो स्वच्छता कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

स्वच्छता अभियान में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरालीबेन नायक, विधायक श्री राकेशभाई देसाई, जिला कलेक्टर श्री मनीष गुरवानी, जिला विकास अधिकारी श्री कार्तिक जीवाणी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राहुल पटेल, पदाधिकारी-अधिकारी, स्थानीय अग्रणी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन जुड़े।

पश्चिम रेलवे में पहली बार वटवा इलेक्ट्रिक लोको शेड को मिला प्रतिष्ठित CII “GreenCo GOLD” रेटिंग सम्मान

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड, वटवा को पर्यावरणीय उत्कृष्टता और सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) – ग्रीन बिजनेस सेंटर (GBC) द्वारा प्रतिष्ठित GreenCo GOLD Rating से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18 जून 2026 को आयोजित 15वें GreenCo Summit 2026 में वरिष्ठ मण्डल मेकेनिकल इंजीनियर वटवा, श्री अशोक कुमार को प्रदान किया। इस उपलब्धि के साथ वटवा शेड देश के अग्रणी हरित एवं सतत संस्थानों में शामिल हो गया है।

मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम),अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने कहा कि “इलेक्ट्रिक लोको शेड, वटवा को प्राप्त प्रतिष्ठित CII GreenCo GOLD Rating पूरे अहमदाबाद मंडल और पश्चिम रेलवे के लिए गर्व का विषय है। यह सम्मान हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और सतत विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है। वटवा शेड ने नवाचार, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाकर यह सिद्ध किया है कि उत्कृष्ट परिचालन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।”

“भारतीय रेल वर्ष 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे विश्वास है कि वटवा इलेक्ट्रिक लोको शेड की यह सफलता भारतीय रेल की अन्य इकाइयों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी तथा हम सभी मिलकर एक सुरक्षित, स्वच्छ, हरित और सतत भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे।”

पश्चिम रेलवे में पहली बार किसी इलेक्ट्रिक लोको शेड को यह प्रतिष्ठित GreenCo GOLD Rating प्राप्त हुई है, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में पश्चिम रेलवे की अग्रणी भूमिका को दर्शाती है।

GreenCo Rating भारत की अपनी तरह की पहली ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है, जो किसी संस्थान के पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन करती है। इसके अंतर्गत ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, अपशिष्ट प्रबंधन, सामग्री संरक्षण एवं पुनर्चक्रण, हरित आपूर्ति श्रृंखला, हरित अवसंरचना एवं पारिस्थितिकी तथा पर्यावरणीय नवाचार जैसे विभिन्न मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। GOLD Rating इस प्रणाली के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है।

ऊर्जा दक्षता एवं स्वच्छ ट्रैक्शन

इलेक्ट्रिक लोको शेड, वटवा ने डीजल आधारित परिचालन से पूर्णतः इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की ओर परिवर्तन करते हुए वर्ष 2022-23 में 1.88 करोड़ लीटर से अधिक डीजल (HSD) की खपत को शून्य पर ला दिया, जिससे Scope-1 उत्सर्जन में लगभग 100 प्रतिशत की कमी आई। प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग हेतु असेंबली बे में लॉन्ग-ट्यूब डेलाइट हार्वेस्टिंग (Brillantor) प्रणाली स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त पारंपरिक पंखों के स्थान पर 5-स्टार रेटेड BLDC पंखे, CFL एवं हैलोजन लाइटों के स्थान पर LED लाइटें, ऑक्यूपेंसी सेंसर तथा एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर का उपयोग कर ऊर्जा बचत सुनिश्चित की गई।

जल संरक्षण की दिशा में नवाचार

वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण प्रणाली के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 20.5 लाख लीटर जल पुनर्भरण की क्षमता विकसित की गई है। लोकोमोटिव के विंडशील्ड वॉशर सिस्टम में अभिनव संशोधन तथा जलरहित यूरिनल की व्यवस्था के माध्यम से जल संरक्षण एवं लोको पायलटों की स्वच्छता सुनिश्चित की गई है। प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट जल एवं उपचारित जल के निष्कासन को शून्य तक लाते हुए ताजे जल की विशिष्ट खपत में निरंतर कमी दर्ज की गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा

अहमदाबाद मंडल में लगभग 1,863 किलोवाट पीक (kWp) क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे प्रतिवर्ष अनुमानित 24.22 लाख यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त वटवा शेड के लिए समर्पित रूफटॉप सौर परियोजना भी प्रस्तावित है। इससे भारतीय रेल के वर्ष 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को बल मिल रहा है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी

Scope-1, Scope-2 तथा Scope-3 के अंतर्गत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता में निरंतर वर्ष-दर-वर्ष कमी दर्ज की गई है। 800 से अधिक जीवित वृक्षों के संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से कार्बन ऑफसेट को भी बढ़ावा दिया गया है।

अपशिष्ट प्रबंधन एवं सामग्री संरक्षण

“Zero Waste to Landfill” दृष्टिकोण अपनाते हुए स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण, अधिकृत पुनर्चक्रण एजेंसियों के माध्यम से निस्तारण तथा ISO 14001 एवं ISO 50001 प्रमाणित प्रबंधन प्रणालियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। वार्षिक औसत खपत (AAC) की समीक्षा एवं पुर्जों के पुनः उपयोग के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 38 लाख रुपये की बचत सुनिश्चित की गई है।

हरित आपूर्ति श्रृंखला एवं नवाचार

ग्रीन प्रमाणित विक्रेताओं से खरीद, पैकेजिंग में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध तथा पैकिंग अपशिष्ट वापसी जैसी व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सादगी खेरगाम तहसील के पाणीखडक गाँव के साधारण किसान के घर लिया रात्रि भोजन

किसान परिवार के आतिथ्य तथा देसी भोजन का आनंद उठाया

गांधीनगर : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रोटोकॉल को परे रखते हुए नवसारी जिले की खेरगाम तहसील के पाणीखडक गाँव के पटेल फळिया (मोहल्ले) में रहने वाले साधारण किसान जितेन्द्रभाई चुनीलाल देसाई के लीपाई वाले घर में जमीन पर बैठकर रात्रि भोजन लिया। उन्होंने हरे-भरे खेतों तथा सर्पाकार रास्तों के बीच स्थित इस छोटे-से घर में 1 वर्षीय बेटी 11 वर्षीय निक्की के हर्ष-उमंग के बीच तथा देसाई परिवार के सभी सदस्यों के साथ काँसे की थाली-प्याली में परोसे गए देसी नागली-चावल के रोटले (बड़ी रोटी), खिचडी, कढी और मिक्स सब्जी का स्वाद लिया।

इस अवसर पर दोनों महानुभावों ने समाज में यह प्रेरणादायी संदेश दिया कि जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, वैसे ही सत्ता एवं पद के बीच भी नम्रता बनाए रखना ही वास्तविक महानता है। सच्ची भव्यता सादगी में है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर मनीष गुरवानी, जिला विकास अधिकारी श्री कार्तिक जीवाणी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राहुल पटेल और अन्य पदाधिकारियों ने अत्यंत शांत एवं आतिथ्यपूर्ण वातावरण में भोजन करके सामान्य परिवार के आतिथ्य का सम्मान कर आम जनता के प्रतिनिधि होने की प्रतीति कराई।

वडोदरा स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

पश्चिम रेलवे के वडोदरा स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु लिए जा रहे मेजर ब्लॉक के कारण 21 जून, 2026 से 08 जुलाई, 2026 तक कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

21 जून, 2026 से 08 जुलाई, 2026 तक निम्नलिखित ट्रेनें प्रभावित रहेंगी

शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें

▶▶ ट्रेन संख्या 19036 अहमदाबाद–वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बाजवा–वडोदरा के आंशिक बीच निरस्त रहेगी।

▶▶ ट्रेन संख्या 22960 जामनगर–वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बाजवा–वडोदरा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

▶▶ ट्रेन संख्या 69114 वटवा–वडोदरा मेमू बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बाजवा–वडोदरा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

▶▶ ट्रेन संख्या 69108 वटवा–वडोदरा मेमू बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बाजवा–वडोदरा के बीच निरस्त रहेगी।

▶▶ ट्रेन संख्या 69102 वटवा–वडोदरा मेमू बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बाजवा–वडोदरा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें

▶▶ ट्रेन संख्या 19035 वडोदरा–अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

▶▶ ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा–जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

▶▶ ट्रेन संख्या 69101 वडोदरा–वटवा मेमू बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

▶▶ ट्रेन संख्या 69115 वडोदरा–वटवा मेमू बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

▶▶ ट्रेन संख्या 69113 वडोदरा–वटवा मेमू बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच निरस्त आंशिक रहेगी।

▶▶ ट्रेन संख्या 69107 वडोदरा–वटवा मेमू बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा–बाजवा के बीच निरस्त आंशिक रहेगी।

प्रारंभिक स्टेशन में परिवर्तन

▶▶ ट्रेन संख्या 59549 वडोदरा–वटवा मेमू वडोदरा के स्थान पर प्रतापनगर स्टेशन से 05.40 बजे प्रस्थान करेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा आरंभ करें। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य अद्यतन जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

जून-2026 का मुख्यमंत्री का राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम सोमवार, 22 जून को आयोजित होगा

23 से 25 जून के दौरान आयोजित होने वाले शाला प्रवेशोत्सव के कारण राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ के आयोजन में बदलाव

गांधीनगर, : राज्य के नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित होने वाला मुख्यमंत्री का स्वागत ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम सोमवार, 22 जून को आयोजित होगा।

राज्य में 23 से 25 जून के दौरान आयोजित होने जा रहे शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के चलते जून-2026 का राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) कार्यक्रम गुरुवार के बजाय सोमवार, 22 जून को आयोजित होगा।

इस राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ के लिए अभ्यावेदक सोमवार, 22 जून, 2026 की सुबह 8 से 11 बजे के दौरान अपना अभ्यावेदन मुख्यमंत्री की जनसंपर्क इकाई, स्वर्णिम संकुल-2, गांधीनगर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सोमवार, 22 जून को दोपहर बाद इस राज्य स्तरीय ‘स्वागत’ में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे और उनके निवारण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे।

नवसारी जिले के पाणीखडक गाँव के प्राथमिक विद्यालय में राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का रात्रि विश्राम

▶▶ राज्यपाल ने सुबह-सुबह विद्यार्थियों के साथ किया योग एवं प्राणायाम

▶▶ विद्यार्थी स्वस्थ एवं तेजस्वी भविष्य के लिए दैनिक जीवन में योग तथा प्राणायाम को अवश्य स्थान दें : राज्यपाल

▶▶ योग सत्र में राज्यपाल ने विद्यार्थियों के साथ विभिन्न योग एवं प्राणायाम का प्रायोगिक अभ्यास कर उसके स्वास्थ्योन्मुखी महत्व के विषय में प्रेरक संवाद किया

गांधीनगर : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नवसारी जिले की खेरगाम तहसील के पाणीखडक गाँव में प्राथमिक विद्यालय के साधारण वर्ग खंड (क्लासरूम) में सादगीपूर्ण रात्रि विश्राम किया। उदित हो रहे प्रातःकाल में राज्यपाल ने विद्यालय के विद्यार्थियों, ग्रामीणजनों तथा युवाओं के साथ योगाभ्यास किया।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री के गाँव के अतिथि बनकर ग्रामीण कल्याण के ध्येय के साथ विद्यालय में रात्रि निवास करने के इस प्रेरक दृष्टिकोण से ग्रामीणजनों तथा विद्यालय के स्कूली बच्चों में भारी उत्साह और आनंद का वातावरण देखने को मिला।

सुबह-सुबह (तड़के) आयोजित विशेष योग सत्र में राज्यपाल ने विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ विभिन्न योगासन किए और बच्चों को योग के शारीरिक एवं मानसिक लाभों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है, मन एकाग्र बनता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज के व्यस्त एवं आधुनिक जीवन में योग तथा प्राणायाम स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि योग द्वारा शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित होता है, जिसके कारण मानसिक तनाव दूर होता है और विद्यार्थियों को पढ़ाई में भी अधिक एकाग्रता प्राप्त होती है।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों के साथ कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका तथा मन की शांति एवं ध्यान केन्द्रित करने में सहायक भ्रामरी प्राणायाम का प्रायोगिक अभ्यास किया और उससे श्वसन तंत्र के मजबूत बनने की वैज्ञानिक समझ दी।

राज्यपाल ने बच्चों के साथ अत्यंत स्नेहपूर्वक संवाद साधते हुए उनके अध्ययन, दैनिक गतिविधियों तथा कॅरियर के बारे में मार्गदर्शन दिया और जीवन में अनुशासन, परिश्रम तथा सकारात्मक विचारधारा अपनाकर उत्तम शिक्षा के साथ उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने के लिए आशीर्वचन दिया। पवित्र गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ यह योग सत्र संपन्न हुआ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा धरती माता को हरियाली करने के संकल्प के रूप में दिए गए अभियान ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अंतर्गत राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नवसारी के आदिजाति क्षेत्र आछवणी में वृक्षारोपण किया

▶▶ समग्र राज्य में ‘एक पेड़ माँ के नाम-3.0’ में 8 करोड़ पेड़-पौधे लगाने का लक्ष्य

▶▶ हरियाला गाँव तथा ई-पर्यावरण अंतर्गत आछवणी में विभिन्न 28 प्रजातियों के 1600 पेड़-पौधों का रोपण एवं संरक्षण होगा

▶▶ राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री का नवसारी के आदिजाति गाँवों में रात्रि प्रवास

▶▶ ग्रामसभा में ग्रामीणजनों के साथ संवाद, सामूहिक सफाई तथा प्राकृतिक खेती परिसंवाद

गांधीनगर : राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल नवसारी जिले के आदिजाति क्षेत्र आछवणी में गुरुवार को ‘एक पेड़ माँ के नाम-3.0’ अंतर्गत ग्रामीणजनों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागी हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने धरती माता को हरियाली बनाने के लिए ग्रीन कवर बढ़ाने का आह्वान किया है और प्रत्येक व्यक्ति से ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अंतर्गत अपनी माता की स्मृति में एक वृक्ष लगाने की अपील की है।

प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू कराए गए इस देशव्यापी अभियान के दो चरण पूर्ण हुए हैं और इस वर्ष ‘एक पेड़ माँ के नाम-3.0’ अंतर्गत गुजरात ने 8 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।

इस अभियान के प्रथम चरण में वर्ष 2024 में गुजरात ने 17.50 करोड़ पौधों तथा वर्ष 2025 में दूसरे चरण में 10.96 करोड़ पौधों का रोपण कर अग्रसरता प्राप्त की है।

राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार शाम नवसारी की खेरगाम तहसील के आछवणी गाँव में ग्रामीणजनों के सहयोग से हरियाला गाँव एवं ई-पर्यावरण अंतर्गत वृक्षारोपण किया, जिसमें ‘एक पेड़ माँ के नाम-3.0’ अभियान के तहत विभिन्न 28 प्रजातियों के 1600 पेड़-पौधों का रोपण और संरक्षण किया जाएगा।

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने इस वृक्षारोपण के अतिरिक्त; नवसारी जिले के आदिजाति गाँवों आछवणी एवं पाणीखडक में गुरुवार को रात्रि निवास कर ग्रामसभा में ग्रामीणजनों के साथ संवाद, सामूहिक सफाई और प्राकृतिक खेती के विषय में संवाद-वार्तालाप किया।

‘एक पेड़ माँ के नाम-3.0’ अभियान अंतर्गत वन विभाग ने नवसारी जिले में समग्रतः 42.34 लाख पेड़-पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। नवसारी जिले ने वर्ष 2025-26 में ‘एक पेड़ माँ के नाम-2.0’ अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल 20.38 लाख पौधों का रोपण किया था।

-: राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी :-

इस अवसर पर ग्रामीणजनों को प्रेरित करते हुए राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजी ने कहा कि प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। ग्लोबल वार्मिंग एवं क्लाइमेट चेंज के इस युग में यदि हमें हमारी धरती माता को बचाना है, तो प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही होगा।

उन्होंने रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खेती में प्राकृतिक पद्धतियाँ अपनाने से ही जमीन की उर्वरकता तथा मानव स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान की सराहना करते हुए ग्रामीणजनों का अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और लगाए गए वृक्षों का संतान की तरह जतन करने का आह्वान किया। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि पानी की एक-एक बूंद का संग्रह तथा प्रत्येक नागरिक द्वारा पर्यावरण जतन के लिए उठाया गया एक छोटा कदम भी भविष्य की पीढ़ियों के लिए वरदान सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ग्रामीण स्तर से प्रारंभ हुई यह जनजागृति ही सशक्त एवं समृद्ध भारत के निर्माण की नींव बनेगी।

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रकृति के जतन व संवर्धन पर विशेष बल देते हुए कहा कि यदि हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे, तो ही हम अपने जीवन तथा संस्कृति को सुरक्षित रख सकेंगे। कोरोना काल के मुश्किल समय की याद दिलाते हुए उन्होंने जोड़ा कि प्रकृति ने मानव जाति को एक बड़ा सबक सिखाया है कि चाहे कितना भी धन या वैभव होगा, लेकिन यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो शरीर छोड़ना पड़ेगा और किसी का कुछ नहीं चलेगा।

मुख्यमंत्री ने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नागरिकों से संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने पानी और पेट्रोल बचाने के लिए जागरूक होने की अपील करके जल संचय के महत्व पर बल देते हुए कहा कि राज्य में अधिक से अधिक तालाब बनें और वे पानी से भरें; इसके लिए हम सभी के सामूहिक प्रयास होने चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ पर्यावरण संरक्षण के अभियानों में जन-जन को जोड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के प्रत्येक नागरिक का अपनी माता के नाम पर एक पेड़ लगाने और उसका संरक्षण करने का प्रेरक आह्वान किया।

इस अवसर पर नवसारी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरालीबेन नायक, विधायक श्री राकेशभाई देसाई, जिला कलेक्टर श्री मनीष गुरवानी, जिला विकास अधिकारी श्री कार्तिक जीवाणी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राहुल पटेल, परियोजना प्रशासक श्री स्वप्निल एम. सिसले, वन उप संरक्षक सुश्री उर्वशी प्रजापति, पदाधिकारी-अधिकारी, स्थानीय अग्रणी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

किसानों का आंदोलन कैसे टूटा, इस मुद्दे पर AAP नेता प्रवीण राम, अजीत लोखील और पंकज राणसरिया ने किए खुलासे

- कांग्रेस ने अपनी विफलता छुपाने के लिए किसानों को गुमराह किया: प्रवीण राम AAP
- कांग्रेस के कपट और लालच के कारण किसानों का आंदोलन टूटा: प्रवीण राम AAP
- हम कांग्रेस को चुनौती देते हैं कि यदि गांधीनगर रैली की अनुमति मांगी गई थी तो उसे सार्वजनिक करे, और यदि रैली नामंजूर हुई हो तो उसका पत्र भी सार्वजनिक करे : प्रवीण राम AAP
- हाईटेंशन लाइन के मुद्दे पर भाजपा का विरोध करने की बजाय कांग्रेस ने AAP का विरोध किया: प्रवीण राम AAP
- कांग्रेस ने गांधीनगर तक जाने की अनुमति मांगी ही नहीं थी: प्रवीण राम AAP
- कांग्रेस ने किसानों को गुमराह करने के लिए गांधीनगर की बात की लेकिन अनुमति केवल अहमदाबाद के ओगणज तक की ही ली थी: प्रवीण राम AAP
- अनुमति पत्र में ही लिखा हुआ है कि कांग्रेस की सभा होगी और अमित चावड़ा उपस्थित रहेंगे: प्रवीण राम AAP
- गुजरात के किसान समझें कि कांग्रेस ने किस हद तक किसानों के साथ कपट करने की कोशिश की: प्रवीण राम AAP
- कांग्रेस इसी तरह 30 वर्षों से गुजरात के किसानों को ठगती आई है, इसलिए भाजपा सत्ता में बैठी है: प्रवीण राम AAP
- AAP किसानों के लिए संघर्ष जारी रखेगी, 27 जून को सुरेंद्रनगर में बड़ी "किसान महापंचायत" आयोजित होगी: प्रवीण राम AAP
- फरवरी महीने में शुरू हुए आंदोलन में किसान के बेटे के रूप में मैंने पालभाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन दिया था: पंकज राणसरिया AAP
- कंटारा से मोरबी की रैली का आयोजन हुआ था, वह रैली भी बीच रास्ते में रोक दी गई थी: पंकज राणसरिया AAP
- जेतपुर के किसान स्वामीनारायण गुरुकुल में रात्रि विश्राम करके रात 3:30 बजे रैली के लिए निकलने वाले थे, तो उन्हें सुबह 9:30 बजे तक कांग्रेस नेताओं ने क्यों नहीं निकलने दिया ?: पंकज राणसरिया AAP
- ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस के नेता अचानक कांग्रेस का खेस पहनकर आए और विवाद खड़ा किया: पंकज राणसरिया AAP
- 14 तारीख को सभा की अनुमति मिल जाने के बावजूद भी आखिरी समय तक किसानों को नहीं बताया गया कि रैली गांधीनगर नहीं जाएगी: पंकज राणसरिया AAP
- हमने कांग्रेस नेताओं से कहा था कि कांग्रेस के झंडे उतार लो तो किसान सभा में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर भी उन्होंने कांग्रेस के झंडे नहीं हटाए: पंकज राणसरिया AAP
- मैंने हाथ जोड़कर कांग्रेस नेताओं से कहा कि किसानों की एकता को तोड़ने का प्रयास न करें: पंकज राणसरिया AAP

अहमदाबाद/राजकोट/मोरबी/जूनागढ़/गांधीनगर/गुजरातः किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी द्वारा सबूतों के साथ बड़ा खुलासा किया गया। आम आदमी पार्टी के फ्रंटल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण राम, प्रदेश संगठन मंत्री अजीत लोखील और किसान नेता पंकज राणसरिया ने राजकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश फ्रंटल अध्यक्ष प्रवीण राम ने पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ कारणों से आज हमें गुजरात कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही गलत जानकारी के बारे में सच्चाई जनता के सामने रखना जरूरी हो गया है। हमारी आम आदमी पार्टी की लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। हम भाजपा की नीतियों और सरकार के खिलाफ सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन पिछले चार-पांच दिनों से कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर झूठे आरोप लगा रही है। इसलिए आज हमारे लिए यह बताना जरूरी हो गया है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, आंदोलन किसने तोड़ा और किन गलत फैसलों के कारण आंदोलन विफल हुआ, यह सबूतों के साथ बताना आवश्यक है। गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने किसानों को गांधीनगर कूच का ऐलान किया था। किसानों से कहा गया था कि गांधीनगर तक जाना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधीनगर तक की रैली के लिए आवश्यक अनुमति ली ही नहीं गई थी। यह एक वास्तविक तथ्य है। आज कांग्रेस भूल गई है कि गुजरात में सत्ता किसके पास है। किसानों के मुद्दों पर भाजपा का विरोध करने की बजाय कांग्रेस आम आदमी पार्टी का विरोध करने में व्यस्त हो गई है। भाजपा से लड़ने की बजाय वे आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाने में समय बिता रहे हैं। किसानों के हाई टेंशन लाइन के मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन के दौरान किसानों को गांधीनगर तक जाने नहीं दिया गया और अहमदाबाद में ही आंदोलन रुक गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके चार महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने किसानों को गांधीनगर कूच का ऐलान किया, लेकिन गांधीनगर तक की अनुमति ली ही नहीं। कांग्रेस ने केवल ओगणज तक की रैली के लिए अनुमति ली थी। यदि अनुमति ही नहीं हो तो आगे कौन जाने देगा? यह केवल आरोप नहीं है। हमारे पास इसके सबूत हैं। पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद द्वारा दी गई अनुमति के दस्तावेजों में स्पष्ट लिखा है कि रैली शांतिपुरा सर्कल से बोपल सर्कल, शिलज सर्कल, भाडज सर्कल होते हुए ओगणज तक जाएगी। इसके बाद वहां सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। अनुमति दस्तावेजों में यह भी उल्लेख है कि सार्वजनिक सभा में गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अमित चावड़ा उपस्थित रहेंगे। यानी स्पष्ट है कि कांग्रेस ने केवल ओगणज तक की रैली और वहां सभा के लिए अनुमति ली थी, जबकि किसानों को गांधीनगर कूच के नाम पर बुलाया गया था। जब किसानों को समझ में आया कि उन्हें गांधीनगर नहीं ले जाया जाएगा और कांग्रेस की सभा में रोका जा रहा है, तब उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। किसानों के सवालों के जवाब में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गांधीनगर जाने की अनुमति नहीं मिली थी।

'आप' नेता प्रवीण राम ने आगे कहा कि सवाल यह है कि यदि अनुमति मांगी ही नहीं गई थी तो मिलेगी कैसे? यदि कांग्रेस ने वास्तव में गांधीनगर तक जाने की अनुमति मांगी थी और सरकार द्वारा इनकार किया गया था, तो उससे संबंधित 'नामंजूरी' का लिखित पत्र जनता और किसानों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। यदि अनुमति नहीं मिली थी तो सरकार का नामंजूरी पत्र दिखाइए। केवल मौखिक दावों से काम नहीं चलेगा। यदि कांग्रेस ने किसानों को गुमराह किया है तो उसे यह बात स्वीकार करनी चाहिए। यदि किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। झूठे आरोप और भ्रामक बयान देने की बजाय कांग्रेस को तथ्य सार्वजनिक करने चाहिए और किसानों के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने बाद में यह कहना शुरू कर दिया कि हम तो केवल नाश्ते के लिए रुके थे। लेकिन जब किसानों ने सवाल पूछना शुरू किया कि यहां मंच क्यों बनाया गया है? कुर्सियां क्यों लगाई गई हैं? तो उनके पास इसका कोई उचित जवाब नहीं था। यदि केवल नाश्ते के लिए ही रुकना था तो फिर सार्वजनिक सभा की अनुमति क्यों ली गई? कागज पर सार्वजनिक सभा की अनुमति ली गई थी और उसमें कांग्रेस नेताओं के संबोधन का भी उल्लेख किया गया था। यह स्पष्ट सबूत है कि वहां केवल नाश्ते का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। गुजरात के किसानों को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस ने किस हद तक उन्हें गुमराह करने की कोशिश की है। किसानों के नाम पर आंदोलन खड़ा करके उनका उपयोग किया गया। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई। जब उनकी अपनी गलतियां और विफलताएं सामने आईं, तब उसका दोष आम आदमी पार्टी और अन्य लोगों पर डालने का प्रयास किया गया। जब किसान नाराज हुए, विरोध व्यक्त किया और सवाल पूछने लगे, तब कांग्रेस ने पूरी घटना का दोष आम आदमी पार्टी और पंकज राणसरिया पर डालने का प्रयास किया। मानो कांग्रेस को दिन-रात केवल आम आदमी पार्टी ही दिखाई देती हो। यदि आपने किसानों को पहले ही बता दिया होता कि कांग्रेस की सभा में जाना है, कांग्रेस के झंडों और बैनरों वाला कार्यक्रम है, तो किसान अपना निर्णय स्वयं ले सकते थे। लेकिन उन्हें गांधीनगर कूच के नाम पर बुलाया गया और ओगणज के पास ही रोक दिया गया। स्वाभाविक है कि किसानों में आक्रोश फूटे और वे सवाल पूछें। पंकज राणसरिया पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह झूठे हैं। पंकज राणसरिया कार्यक्रम वाले दिन अचानक उपस्थित नहीं हुए थे। वे किसानों के समर्थन और सहयोग के लिए रैली में शामिल हुए थे। जब किसानों में असंतोष फैला और वे सवाल पूछने लगे, तब पंकज राणसरिया किसानों के साथ खड़े रहे। एक किसान पुत्र के रूप में उन्होंने किसानों की भावनाओं और सवालों को आवाज दी। क्या यह उनका अपराध है?

प्रवीण राम ने आगे कहा कि पंकज राणसरिया के पास इस संबंध में वीडियो सबूत भी हैं। उन वीडियो में वे कांग्रेस नेताओं से कहते हुए दिखाई देते हैं कि यदि यह वास्तव में किसानों का कार्यक्रम है तो कांग्रेस के झंडे और बैनर हटा दीजिए। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने ऐसा नहीं किया। यदि किसानों का कार्यक्रम खराब करने का इरादा नहीं होता तो किसानों की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया होता। इससे स्पष्ट होता है कि कार्यक्रम में विवाद और भ्रम पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन था। मेरी कांग्रेस को केवल एक सलाह है कि आम आदमी पार्टी का विरोध करने के बजाय भाजपा का विरोध करो। भाजपा के खिलाफ लड़ो। पिछले तीस वर्षों से गुजरात में भाजपा सत्ता में है। किसानों, युवाओं और आम जनता के मुद्दों के लिए लड़ने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है लेकिन गुजरात के किसानों के मुद्दों के लिए लगातार संघर्ष करती रही है। हमने किसानों के अधिकारों के लिए 108 दिनों तक जेल भी काटी है। कांग्रेस के कितने नेताओं ने किसानों के लिए ऐसा त्याग किया है? कांग्रेस को अभी भी समय रहते समझना चाहिए कि हमारा विरोध करने का कोई अर्थ नहीं है। हम सत्ता में नहीं हैं। गुजरात में सत्ता भाजपा की है। यदि विरोध करना है तो भाजपा का करो, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी उनकी है, आम आदमी पार्टी की नहीं। यदि वास्तव में लड़ाई लड़नी है तो भाजपा के खिलाफ लड़ो। हम तो अपनी लड़ाई जारी रखने वाले हैं। पूरी ताकत के साथ लड़ने वाले हैं। गुजरात के किसानों के अधिकार और न्याय के लिए लड़ने वाले हैं। आगामी 27 तारीख को सुरेंद्रनगर में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। आने वाले दिनों में गुजरात के किसानों को न्याय दिलाने के लिए भी हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 14 तारीख को जब रैली के लिए अनुमति मिल गई थी, तब गुजरात के किसानों को सही जानकारी क्यों नहीं दी गई? उन्हें यह क्यों नहीं बताया गया कि अनुमति केवल ओगणज तक की है और गांधीनगर तक की नहीं? किसानों को अंधेरे में क्यों रखा गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में गुजरात के किसान कांग्रेस से जरूर मांगेंगे। गुजरात के किसानों को गुमराह करना बंद करें। आंदोलन टूटने के पीछे आपकी गलतियां, आपका लालच और आपकी कपटपूर्ण राजनीति जिम्मेदार है। गुजरात के किसानों के साथ जो विश्वासघात हुआ है, उसका जवाब आने वाले दिनों में किसान जरूर मांगेंगे।

इस अवसर पर आम आदमी पार्टी और किसान नेता पंकज राणसरिया ने कहा कि मैं कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं कि फरवरी महीने की दूसरी तारीख को किसानों की पहली रैली का आयोजन पालभाई द्वारा किया गया था। उस समय से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी की टीम ने किसानों के हित में लगातार सहयोग दिया है। 2 फरवरी को मोरबी तक जो ट्रैक्टर रैली आयोजित की गई थी, उसमें पंकज राणसरिया और हमारी पूरी टीम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हुई थी। पालभाई ने हमेशा किसानों के अधिकारों के लिए स्पष्ट रूप से काम किया है और हमने भी उन्हें पूरा सहयोग दिया है। इस रैली के दौरान कई स्थानों पर किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई गई थी। हालांकि मोरबी से तीन किलोमीटर दूर एक क्षेत्र में पुलिस द्वारा रोक दिया गया था और वहीं किसानों को रोक लिया गया था। उस समय भी किसानों के साथ अन्याय हुआ था। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन परिस्थितियों के कारण रैली आगे नहीं बढ़ सकी थी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के कुछ नेता केवल थोड़े समय के लिए उपस्थित रहे थे और उसके बाद वे कलेक्टर साहब से मिलने चले गए थे। जबकि किसान वहीं मौजूद रहे और अपनी मांगों के लिए आवाज उठाते रहे। इस पूरी घटना में किसानों के हित की अनदेखी की गई थी, यह स्पष्ट होता है। इसके बाद के चरण में, जेतपर गांव में 15 तारीख के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने हेतु हम और हमारी टीम विभिन्न गांवों में गए थे। यह कार्यक्रम किसानों के हित में आयोजित किया गया था और इसमें स्थानीय स्तर पर भी व्यापक सहयोग मिला था। हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि पिछले चार महीनों से हमारी टीम किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार मैदान में रही है। हर कार्यक्रम में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया गया है। सभी दावों और आरोपों के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं। मेरा नाम लेकर भी कांग्रेस नेताओं द्वारा गलत प्रस्तुति की जा रही है, जबकि मेरी कोई सीधी भूमिका न होने के बावजूद मेरा नाम मीडिया और बयानों में लिया जा रहा है। जब रैली का समापन हुआ, उसके बाद मीडिया द्वारा सवाल पूछे गए, तब भी पालभाई आंबलिया ने मेरा नाम लेने में संकोच किया और आसपास खड़े लोगों से पूछने के बाद मेरा नाम लिया।

मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि पालभाई से मेरा एक सवाल है। जेतपर गांव और आसपास के गांवों से जो किसान आए थे, उन्हें स्वामीनारायण गुरुओं के स्थान पर रात्रि विश्राम कराया गया था। वहां से इन किसानों को सुबह 3:30 से 4:00 बजे के बीच निकलने की योजना थी, ताकि वे सुबह 9:30 बजे तक शांतिपुरा सर्कल पहुंच सकें। लेकिन हकीकत यह है कि स्वामीनारायण मंदिर परिसर से किसानों को समय पर बाहर निकलने नहीं दिया गया। किसानों को वहीं रोके रखा गया और उन्हें लगभग सुबह 9:30 बजे तक वहां से निकलने की अनुमति नहीं दी गई। इस संबंध में मेरे पास वीडियो सबूत भी हैं, जिनमें कांग्रेस के कुछ नेता स्वयं स्वीकार करते दिखाई देते हैं कि किसानों को सुबह 3:30 बजे निकलना था, लेकिन उन्हें समय पर बाहर निकलने नहीं दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में किसानों को पीछे रखा गया और उनके कार्यक्रम की गति को रोका गया। इस बारे में कांग्रेस की ओर से स्पष्टता दी जानी चाहिए कि किसानों को समय पर बाहर क्यों नहीं निकलने दिया गया। हम कांग्रेस से इन सवालों के जवाब मांगते हैं और किसानों को हुई असुविधा के बारे में सच्चाई जनता के सामने रखी जाए, ऐसी मांग करते हैं। शांतिपुरा सर्कल पर अलग-अलग गांवों के किसान बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। मैं भी किसान का बेटा होने के नाते सुबह लगभग नौ बजे वहां पहुंच गया था। इसके बाद साढ़े दस से ग्यारह बजे के बीच अचानक कांग्रेस प्रदेश के कुछ पदाधिकारी और नेता कांग्रेस का खेस पहनकर वहां पहुंचे। इस पूरे आंदोलन के शुरू में यह कांग्रेस का कार्यक्रम है, इसकी जानकारी किसानों को नहीं थी। वहां मौजूद कई लोग किसान प्रतिनिधि के रूप में और किसानों के समर्थन में आए थे। वहां आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी किसानों के हित में उपस्थित थे। लेकिन इसके बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा स्थिति को अपने पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयास किया गया और कार्यक्रम को कांग्रेस का स्वरूप देने की कोशिश की गई। मैं भी किसान का बेटा होने के नाते वहां मौजूद था और किसानों के हित में आंदोलन का समर्थन करने आया था, किसी पार्टी की सभा में भाग लेने नहीं। मैंने स्वयं कांग्रेस के कुछ नेताओं से अनुरोध किया था कि यदि यह वास्तव में किसानों का आंदोलन है तो मंच पर लगाए गए कांग्रेस के बैनर और झंडे हटा दिए जाएं, ताकि किसान निष्पक्ष रूप से अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें। मैंने हाथ जोड़कर भी अनुरोध किया था कि किसानों की एकता को तोड़ने का प्रयास न किया जाए। लेकिन इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और स्थिति को और अधिक राजनीतिक रंग दिया गया। मेरे पास ऐसा वीडियो भी है जिसमें मैं स्पष्ट रूप से कहता दिखाई देता हूं कि यदि कांग्रेस के बैनर और झंडे हटा दिए जाएं तो किसान कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात आगे रख सकते हैं। फिर भी इस बात की अनदेखी की गई। इस घटना से स्पष्ट होता है कि किसानों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने और उसकी दिशा बदलने का प्रयास किया गया। किसानों को सही जानकारी नहीं दी गई और उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया गया। सुबह मीडिया बाइट में भी यह दिखाया गया कि किसान यहां से गांधीनगर की ओर जाएंगे, जबकि वास्तव में किसानों को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को पहले से ही जानकारी थी कि किसानों को गांधीनगर नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन फिर भी किसानों को अंधेरे में रखा गया।

मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के खजाने से हजारों करोड़ रुपये के दान और आभूषण गायब होने के गंभीर आरोप लगे हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

अयोध्या के राम मंदिर से लाखों रुपये की चोरी का मामला अभी ताजा ही है, ऐसे में मथुरा के प्रसिद्ध संत दिनेश फलाहारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के खजाने (तोषा खाना) से हजारों करोड़ रुपये के आभूषण और दान की वस्तुएं चोरी हो गई हैं।

यह मामला अयोध्या की स्थिति को दर्शाता है। अयोध्या में राम मंदिर के दान में कथित अनियमितताओं और धोखाधड़ी को लेकर विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से दान की गई धनराशि की बड़े पैमाने पर चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले के मुख्य शिकायतकर्ता पंडित दिनेश फलाहारी ने मथुरा मंदिर प्रशासन और तत्कालीन प्रशासकों पर हजारों करोड़ रुपये के दान, सोने-चांदी के आभूषणों और कीमती सामानों की चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए मंदिर के खजाने को निशाने पर ले लिया है। पंडित दिनेश फलाहारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई द्वारा इस पूरे मामले की तत्काल उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कई दशकों बाद जब मंदिर के ऐतिहासिक खजाने (तोशाखाना) को हाल ही में खोला गया, तो सभी लोग अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गए। आरोप है कि खजाने में रखे बक्से पूरी तरह खाली थे और उनमें राजाओं, महाराजाओं और देश-विदेश के भक्तों द्वारा दान किए गए अनमोल हीरे, रत्न और सोने के आभूषण नहीं मिले। इसके अलावा, मंदिर की कई चल और अचल संपत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं।

इस प्रकार, मथुरा में "राम मंदिर के दान की चोरी" जैसी घटनाओं के दावों ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजनीति और मंदिर प्रशासन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो लोगों की ईश्वर में आस्था पर सीधा प्रहार है।

आरोप है कि बेरोजगारी, गरीबी और मुद्रास्फीति के कारण युवा और महिलाएं गलत रास्ते पर धकेले जा रहे हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

शहर में पुलिस की छापेमारी के दौरान, कई युवक-युवतियों को होटलों, गेस्ट हाउसों आदि में अनैतिक धंधे करते हुए पकड़ा गया। लेकिन ये युवतियां इस अनैतिक धंधे में मजबूर और बेबस थीं। इनमें से अधिकतर युवतियां शिक्षित हैं, लेकिन बेरोजगार हैं और बेरोजगारी व काम न मिलने के कारण गरीबी में जीवन यापन कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए घर में आग जलाना भी मुश्किल है।

ऐसी स्थिति में, जब उनके परिवार को दिन का दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता, तो वे दो वक्त के लिए ऐसे घिनौने धंधों का सहारा लेते हैं। इसमें उनकी गरीबी और मजबूरी अहम भूमिका निभाती है। इसमें खासकर भ्रष्टाचार करके धनवान बने राजनेता और उच्च अधिकारी तथा उनके आश्रित ऐसी मजबूर लड़कियों का पूरा फायदा उठाते हैं। और ऐसे अनैतिक धंधों में पैसा लड़कियों को मनोरंजन का साधन बना देता है। और इस तरह वे उनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं। इसमें खासकर राजनेता, उद्योगपति और उच्च अधिकारी

ऐसे मनोरंजन के लिए विदेश जाते हैं और मौज-मस्ती करते हैं। देश में बढ़ती नशे की लत के कारण युवा नशे के आदी हो रहे हैं। क्योंकि न काम है, न धंधा है, न नौकरी है और न ही असहनीय महंगाई में जीने का कोई साधन है, ऐसी स्थिति में युवा नशे के आदी होकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं।

मौजूदा महंगाई में परिवार चलाना असहनीय हो गया है, जबकि देश में करोड़ों शिक्षित उम्मीदवार बेरोजगार हैं। और इस बेरोजगारी के चलते नशे की लत में फंसे युवाओं से कोई यह पूछने तक को तैयार नहीं है कि वे ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों हैं। नेता और उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसों से युवतियों को ऐसे अनैतिक धंधों में धकेलते हैं। क्या आज तक किसी ने ऐसी मजबूरी का शिकार शिक्षित युवतियों से पूछा है कि वे इस जाल में क्यों फंसी हुई हैं?

देश में नेताओं की वजह से अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से करोड़ों रुपये की ड्रग्स जब्त की जाती हैं। अगर युवाओं को समय पर काम, नौकरी और रोजगार मिल जाए, तो वे ऐसे धंधों में क्यों पड़ जाते हैं?